

# दि कर्मिक पोस्ट

Global  
School Of  
Excellence,  
Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 33

( प्रति बुधवार ), इन्दौर, 6 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

## आंध्र प्रदेश में पुराने कोयला बिजली संयंत्रों से मुक्ति, लोगों को पहुंचाएगी 76 हजार करोड़ का फायदा

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार पुराने कोयला बिजली संयंत्रों को रिटायर करके आने वाले दशक में 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर सकती है। इसका फायदा पर्यावरण के साथ-साथ आम लोगों तक भी पहुंचेगा। यह जानकारी थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट रिटायरिंग टू सेव में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से किया गया यह बदलाव न केवल राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा।

गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश में बिजली वितरण कंपनियां पहले ही भारी वित्तीय घाटे से जूझ रही हैं। यदि मई 2022 तक के आंकड़ों को देखें तो इन बिजली कंपनियों को हुआ घाटा बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। ऐसे में यह विश्लेषण राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए रोडमैप प्रस्तुत करता है। जानकारी मिली है कि महंगे पड़ रहे इन कोयला संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा में बदलने से जहां उपभोक्ताओं को इसका फायदा पहुंचेगा और उन्हें सस्ती बिजली मिल पाएगी। वहीं इससे बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ आंध्रप्रदेश को अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद मिलेगी।

जलवायु लक्ष्यों और सरकारी

नीतियों के भी अनुरूप है यह बदलाव- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए आदेश को देखते हुए भी यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि इस आदेश के तहत सरकार ने सभी नए कोयला बिजली संयंत्रों को अपनी क्षमता के 40 फीसदी के बराबर अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का निर्देश दिया था। इस रिपोर्ट में तीन प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला है जो आंध्र प्रदेश को ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। इनमें पहला राज्य में सरप्लस होती कोयला बिजली क्षमता, दूसरा बैटरी स्टोरेज की गिरती लागत के साथ सस्ती अक्षय ऊर्जा और तीसरा 2025 तक अनिवार्य रूप से कोयला बिजली संयंत्रों में बदलाव है। इस बारे में क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के सीईओ आशीष फर्नांडीस का कहना है कि अपने प्रचुर अक्षय ऊर्जा संसाधनों और नीतियों के साथ ध्यान से बनाई योजनाओं और निवेश की मदद से आंध्र प्रदेश पुराने कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर सकता है। देखा जाए तो इसके चलते बिजली कंपनियों और राज्यों को लम्बे समय तक वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। अनुमान है कि कडप्पा और विजयवाड़ा में 1,680 मेगावाट के कुल आठ कोयला ऊर्जा संयंत्रों को रिटायर करने से पांच वर्षों में 9,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इनमें रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन और डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। रिपोर्ट का कहना है



कि महंगे कोयला बिजली संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा में बदलने से उपभोक्ताओं को भी अच्छी-खासी बचत होगी। अनुमान है कि जिन कोयला संयंत्रों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमत चार रुपए प्रति किलोवाट घंटा या उससे ज्यादा है, यदि उसे सस्ती अक्षय ऊर्जा से बदल दिया जाए तो इससे दस वर्षों में करीब 57,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

इस बारे में रिपोर्ट से जुड़े शोधकर्ता विष्णु तेजा के अनुसार

पिछले दशक बिजली क्षमता में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के चलते राज्य में अब पर्याप्त बिजली और उत्पादन क्षमता है। यही वजह है कि राज्य में कोयला संयंत्र 60 फीसदी से भी कम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यदि पुरानी इकाइयों को रिटायर कर भी दिया जाए तो इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

ऐसे समय में जब राज्य का बजट दबाव में है, तब इस सुनियोजित ऊर्जा परिवर्तन से जो

बचत होगी, उसका उपयोग इन बजटीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

देखा जाए तो यह बचत न केवल राज्य की आय में वृद्धि करेगी साथ ही कृषि के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त वाटर पंप और किसानों को नकद हस्तांतरण करने में मददगार हो सकती है। इतना ही नहीं इसकी मदद से छतों पर करीब दो करोड़ सोलर इंस्टालेशन करने में मदद भी मिलेगी।

### मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ युवा उद्यमी ने पौध-रोपण किया

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में युवा उद्यमियों के साथ बरगद, मौलश्री और कदंब के पौधे लगाए। जबलपुर के सर्वश्री आशीष अहिरवार, कमल ठाकुर और नीरज ठाकुर पौध-रोपण में शामिल हुए। युवा उद्यमी श्री आशीष अहिरवार ने मोबाइल चार्जिंग केबल निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत होने की खुशी में पौधे लगाए। वे आईटी पार्क जबलपुर में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित कर रहे हैं।



## उत्तर भारत में रोपाई धान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए सरकार

मुंबई। सरकार को धान की सीधी बुआई के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए सरकार को धान की सीधी बुआई के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए। सरकार को धान की सीधी बुआई के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए। जल ऊर्जा का भंडार, पोषक तथा जीवनदाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं और साथ ही पीने योग्य जल धरती पर अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। विश्व स्तर पर जन जागरूकता अभियान जारी है।

जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है- वनों, झीलों, नदियों, भुजल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। केन्द्रीय भुजल बोर्ड व जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सघन कृषि क्षेत्र वाले उत्तरी राज्यों पंजाब- हरियाणा में पिछले 50 वर्षों से लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने के कारण भुजल स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष गिरने से इन राज्यों के आधे से ज्यादा ब्लॉक गंभीर भुजल संकट में आ चुके हैं। इसे रोकने के लिए, इन राज्यों ने वर्ष 2009 में हरियाणा

और पंजाब प्रिज़र्वेशन आफ सबसायल वाटर एक्ट बनाए, जिसमें 15 जून से पहले धान फसल की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इन सब सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी तक जल संरक्षण खासतौर पर भुजल संरक्षण के प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। यह सर्वविदित है कि 1970 तक उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के साथ लगते मैदानी खादर व तराई क्षेत्रों में भूजल भूमि सतह के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन हरित क्रांति दौर की सघन कृषि तकनीक विशेष तौर पर रोपाई धान, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण आदि से भूजल का अंधाधुंध दोहन होने से गंभीर भूजल संकट बनता जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन उपयोगी जल की उपलब्धता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आदिकाल से सभी अनाज, दलहन, तिलहन आदि फसलों की खेती के लिए, वत्त खेत को तैयार करके बीज की सीधी बुआई प्रचलित तकनीक रही है। वर्ष-1966 से पहले, संयुक्त पंजाब और उत्तर भारत में भी किसान सीधी बुआई से ही धान की खेती किया करते थे। तब धान का क्षेत्रफल कम होने व सस्ते मजदूर मिलने से निराई-गुड़ाई से खरपतवार

नियंत्रण किया जाता था लेकिन सरकार ने हरित क्रांति दौर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान-मनीला से धान की उन्नत बौनी किस्मों के साथ, भूजल बर्बादी वाली खड़े पानी वाली रोपाई धान तकनीक आयात करके उत्तर भारतीय किसानों पर थोप दी। इससे धान की पैदावार तो जरूर बढ़ी, लेकिन खेती लागत में भी कई गुणा बढ़ोतरी और भूजल की भयंकर बर्बादी हुई, जिससे जम्मू से पटना तक सतलुज, यमुना, गंगा नदियों के मैदानी क्षेत्रों में भूजल डार्क ज़ोन में चला गया। धान रोपाई से भयंकर भूजल बर्बादी को रोकने के लिए जहां कृषि वैज्ञानिकों ने इस सदी की शुरुआत में सूखे खेत में धान की सीधी बुआई तकनीक को प्रसारित किया, जिसे किसानों ने पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इस पद्धति में सिंचाई पानी की बचत नहीं होने और फसल बुआई के तुरंत बाद सिंचाई और फिर हर तीन दिन बाद सिंचाई लगाने से फसल में खरपतवार की बहुतायत होने से किसान परेशान हो गए। दूसरी ओर सरकार ने तकनीकी तौर पर अव्यावहारिक योजनाओं (धान छोड़े मक्की बोये, धान खेत खाली रखने वाले किसान को 7000 रुपए/एकड़ प्रोत्साहन राशि, सुक्ष्म सिंचाई, फसल विविधकरण आदि) से किसानों को भ्रमित किया। विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार

150 दिन की धान फसल को मात्र 500-700 मिलीलीटर सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। जिसमें आधे से ज्यादा सिंचाई जल की पूर्ति मॉनसून वर्षा करती है। लेकिन हरित क्रांति दौर में सरकार द्वारा अनुशंसित भूजल बर्बादी वाली रोपाई धान तकनीक में 1500-2000 मि.ली. सिंचाई जल की जरूरत होती है।

इससे खेती लागत में बढ़ोतरी और ऊर्जा-भूजल संसाधनों की भारी बर्बादी हुई। जिसे रोकने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय केन्द्र करनाल की हमारी टीम ने वर्ष-2014-15 में तर-वत्त सीधी बिजाई धान तकनीक को विकसित करके किसानों में प्रसारित किया, जिससे खरपतवार नियंत्रण आसान हुआ और पैदावार रोपाई धान के बराबर ही मिलने लगी। इसके असर से कोरोना आपदा काल वर्ष-2021 में प्रवासी मजदूरों की भारी कमी से पंजाब में किसानों ने लगभग 6 लाख हेक्टेयर यानि कुल धान क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र में तर-वत्त सीधी बुआई तकनीक से धान फसल सफलता से उगाई और प्रदेश में रिकार्ड 12.78 मिलियन टन धान का उत्पादन हुआ। इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दी गई जानकारी के अनुसार खरीफ-2022 में हरियाणा में किसानों ने 72,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर सीधी

बिजाई धान तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाकर 31,500 करोड़ लीटर यानि लगभग 40 लाख लीटर /एकड़ भूजल की बचत की। इसके लिए सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि किसानों को बांटी। अब हरियाणा सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के इन प्रयासों को गति देने के लिए, भूजल बर्बादी वाली रोपाई धान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर सीधी बिजाई धान पद्धति को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे 40 लाख लीटर प्रति एकड़ भूजल के साथ-साथ ऊर्जा (बिजली और डीजल) की भारी बचत होगी। तर-वत्त सीधी बिजाई धान पद्धति में खेत में पानी खड़े की जरूरत नहीं होने से रोपाई धान के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत भूजल की बचत होती है। तर-वत्त सीधी बिजाई धान की सफलता के लिए, धान फसल की बुआई 20 मई से 5 जून तक मूंगा, अरहर, ज्वार आदि खरीफ फसलों की तरह, पलेवा सिंचाई के बाद तैयार तर-वत्त खेत में 8 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से 7-9 इंच लाइन से लाइन दूरी और बीज की गहराई मात्र 1-2 इंच पर होती है। बुआई से पहले 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलो बीज उपचार जरूर करें। खेत की नमी को बचाने के लिए, बुआई शाम के समय पर छोट्य विधि या सीड ड्रिल की मदद से करें और खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद एक लीटर पेंडामेथलीन 30 ई.सी. 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करें।

## पलामू के कौशल का पर्यावरण प्रेम है अद्भुत, घर की छत पर बनाया आकाश बाग

पलामू, जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के रहने वाले पर्यावरणविद कौशल किशोर जयसवाल ने अपने घर की छत पर आकाश बाग का निर्माण किया है। उन्होंने पूरे घर की छत पर तरह-तरह के पेड़-पौधा लगाए हैं। जिसे नियमित रूप से सिंचते और देखभाल करते हैं। इसमें उनके परिवार के बांकी सदस्य भी योगदान देते हैं।

कौशल किशोर जयसवाल ने बताया कि शहर के प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इस दूषित पर्यावरण को ऑक्सीजन की मदद से ठीक किया जा सकता है और वह ऑक्सीजन हमें पेड़-पौधों से मिलेगी। शहरी इलाके में 90 फीसदी जमीन का पक्कीकरण हो गया है। ऐसे में घर या इमारत की छतों पर आकाश बाग बनाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। कौशल किशोर जयसवाल के आकाश बाग में गमले में तरह-तरह के पेड़-पौधे लगे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के पौधों के साथ-साथ विदेशी पौधे भी लगाए गए हैं। इनकी छत पर नेपाल का बेल, महाराष्ट्र का बिजदानी आंवला, आस्ट्रेलिया का बारह मासी जामुन, कर्नाटक का चीकू, भूटान का नींबू, थाइलैंड का आम आदि पौधे देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इस पहल से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपने घरों की छतों पर आकाश बाग बनाया है।



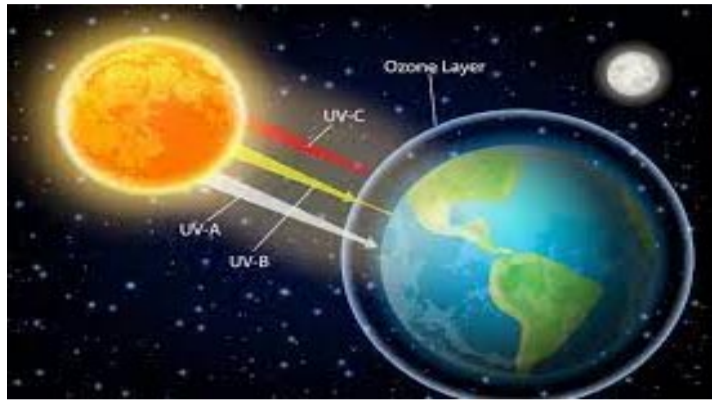
## रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन को कर सकता है कमजोर

नई दिल्ली। धरती को सूर्य से बचाने वाली ओजोन परत को कमजोर करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि कुछ मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। जलवायु में बदलाव करने वाला यह उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है।

अध्ययन के अनुसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधित होने के बावजूद, पांच क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) 2010 से 2020 तक वातावरण में तेजी से बढ़ गए, जो 2020 में रिकॉर्ड-उच्च स्तर तक पहुंच गए। अध्ययन में कहा गया है कि यह वृद्धि शायद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफओ) सहित सीएफसी को बदलने के लिए बने रसायनों के उत्पादन के दौरान रिसाव के कारण हुआ था।

हालांकि मौजूदा स्तरों पर वे ओजोन परत की बहाली के लिए खतरा नहीं हैं, वे वातावरण को गर्म करने वाले अन्य उत्सर्जन में शामिल होकर एक अलग खतरे को बढ़ा सकते हैं। सह-अध्ययनकर्ता इसहाक विमोंट ने कहा, यदि आप इन अगली पीढ़ी के यौगिकों के उत्पादन के दौरान ग्रीनहाउस गैसों और ओजोन को कमजोर करने वाले पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका जलवायु और ओजोन परत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विमोंट, अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लोबल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी में शोधकर्ता है।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक, सीएफसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10 हजार गुना अधिक तेजी से गर्मी को फंसाते हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है



जो जलवायु में बदलाव के लिए जिम्मेवार है।

1970 से 1980 के दशक में, सीएफसी का ठंडा करने के लिए और एयरोसोल स्प्रे में उपयोग किया जाता था। लेकिन इसके उपयोग के कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद का पता चला, जिसके बाद सीएफसी को प्रतिबंधित करने के लिए 1987 में वैश्विक समझौता किया गया। इस समझौते को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, इसके लागू होने के बाद, दुनिया भर में सीएफसी की मात्रा में लगातार गिरावट देखी गई। अध्ययन ने 2010 में दुनिया भर से इसको खत्म करने या वैश्विक फेज-आउट के बिंदु से शुरुआत करते हुए या कुछ वर्तमान में उपयोग की जाने वाले पांच सीएफसी का विश्लेषण किया। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और ग्लोबल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी के सह-अध्ययनकर्ता ल्यूक वेस्टर्न ने कहा कि उन उत्सर्जनों का अब तक ओजोन परत पर मामूली प्रभाव पड़ा है और थोड़ा अधिक प्रभाव जलवायु पर पड़ा है। वे स्विट्जरलैंड के 2020 में सीओ2 उत्सर्जन के बराबर हैं, यह अमेरिका के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग एक प्रतिशत के बराबर है। अध्ययन के मुताबिक प्रत्यक्ष माप शुरू होने के बाद से 2020 में सीएफसी की सभी पांचों गैसों अपनी उच्चतम स्तर पर थीं। लेकिन अगर इसी तरह तेजी जारी रहती है, तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्षों को एक नए तरीके की शुरुआती चेतावनी कहा जिसमें सीएफसी ओजोन परत को खतरे में डाल रहे हैं। उत्सर्जन के उन प्रक्रियाओं के कारण होने की आशंका है जो वर्तमान में

प्रतिबंध और अप्रतिबंधित उपयोगों के अधीन नहीं हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित, उनको बदलने के लिए विकसित औद्योगिक एरोसोल की श्रेणी को अगले तीन दशकों में 1987 की संधि के हालिया संशोधन के तहत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। प्रोटोकॉल ओजोन को कमजोर करने वाले पदार्थों के निकलने पर अंकुश लगाता है जो वातावरण में फैल सकते हैं, लेकिन कच्चे माल या उप-उत्पादों के रूप में अन्य रसायनों के उत्पादन में उनके उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। यह पहली बार नहीं था कि अघोषित उत्पादन का सीएफसी स्तरों पर प्रभाव पड़ा। 2018 में वैज्ञानिकों ने पाया कि सीएफसी की गति पिछले पांच वर्षों की तुलना में आधी हो गई थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि उस मामले में साक्ष्य पूर्वी चीन में कारखानों की ओर इशारा करते हैं। एक बार जब उस क्षेत्र में सीएफसी का उत्पादन बंद हो गया, तो यह वापस पटरी पर आ गया। राष्ट्रव्यापी आंकड़ों की कमी के चलते यह निर्धारित करना मुश्किल है कि गैसों कहां से आ रही हैं और विश्लेषण किए गए कुछ सीएफसी के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं है। वेस्टर्न ने कहा लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के मामले में इन उत्सर्जन को खत्म करना एक आसान जीत है। यह अध्ययन नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

## सरकार को देंगे प्रस्ताव- नदी संरक्षण के लिए बनाए कानून

नर्मदापुरम. बांद्राभान में देश के करीब 12 राज्यों से जुटे विशेषज्ञों ने प्रकृति, संस्कृति और जल, जंगल, जमीन, नदियों के संरक्षण को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मंथन किया। तय किया गया कि नदियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा। नदियों के संरक्षण के लिए नदी घाटी मंच का गठन किया गया। इसमें राजकुमार सिन्हा, किरण देव यादव और इंद्रदेव यादव सहित 5 सदस्यों को राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया गया।

जनआंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय के बांद्राभान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसमें समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से समन्वय बनाकर संघर्ष तेज करने की बात कही गई। दुनिया पर संकट आ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध तत्काल बंद होना चाहिए। इसके परिणाम घातक होने वाले हैं। जीवन का संचार करने वाले हिमालय में लगातार निर्माण कर हम विकास नहीं कहीं ओर जा रहे हैं। हिमालय को निर्माण नहीं संरक्षण की जरूरत है। यह बात प्रसिद्ध पर्यावरणविद् गोल्डमैन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रफुल्ल सामंतारा ने पत्रिका से बातचीत में कही। उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। रासायनिक हथियार के उपयोग से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कृषि, जल, जंगल, जमीन प्रभावित होने लगे हैं। यूक्रेन का अमरीका गठबंधन युद्ध को बंद नहीं होने दे रहा। इसका परिणाम है कि समुद्र की तासीर बदल रही है। दुनिया में भारत की भूमिका इस संघर्ष को बंद कराने वालों की है। इसमें अन्य देशों को शामिल होकर पहल करनी चाहिए।

## कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर शिफ्ट होने से भारत को हर साल होगा 1.6 लाख करोड़ का फायदा

क्या आप जानते हैं कि भारत द्वारा कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर शिफ्ट होना न केवल पर्यावरण बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा। इस बारे में हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि ऊर्जा में इस बदलाव से देश को हर साल 1,950 करोड़ डॉलर यानी करीब 159,169.92 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

हालांकि यह तभी संभव होगा जब भारत अपनी योजना के अनुसार 2025 तक अपने यूटिलिटी स्केल सोलर और विंड पावर में 76 गीगावॉट का इजाफा करने में सफल रहता है। गौरतलब है कि ग्लोबल सोलर पावर और ग्लोबल विंड पावर ट्रैकर द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके हिसाब से भारत को अक्षय ऊर्जा की संभावित क्षमता के मामले में शीर्ष सात देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में 387,258 मेगावॉट के साथ चीन पहले स्थान पर है। देखा जाए तो यदि अगले तीन वर्षों में यदि भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में 76,373 मेगावॉट का इजाफा करने में सफल रहता है तो इससे भारत में हर साल तकरीबन 7.8 करोड़ टन कोयले के इस्तेमाल को टाला जा सकेगा। मोटे तौर पर यह कोयला बिजली संयंत्र क्षमता के करीब 32 गीगावॉट के बराबर है। देखा जाए तो यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मददगार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2030 तक अपनी पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में 420 गीगावॉट का इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यदि भारत अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल रहता है तो भारत में अक्षय ऊर्जा के उपयोग से होने वाली वार्षिक बचत कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। अनुमान है कि इसके चलते कोयले पर घटती निर्भरता के कारण सालाना 5,800 करोड़ डॉलर यानी करीब 473,428.48 करोड़ रुपए की बचत होगी।



नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री



शिवराज सिंह चौहान  
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

## अन्नदाताओं के हित में समर्पित मध्यप्रदेश सरकार

- गेहूँ निर्यात में 46% की भागीदारी (21 लाख मीट्रिक टन से अधिक निर्यात) के साथ मध्यप्रदेश देश में नं. 1
- फसलों के उपार्जन के लिए ₹ 94 हजार 394 करोड़ किसानों को दिए गए
- 0% ब्याज दर पर किसानों को ₹ 47 हजार 745 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण
- किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में ₹ 37 हजार 522 करोड़ का अनुदान
- पीएम किसान सम्मान निधि एवं सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹ 10 हजार की मदद
- 1 लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हेतु 60 हजार से अधिक किसान रजिस्टर्ड
- मध्यप्रदेश सरकार ने ₹ 17 हजार करोड़ से अधिक के बीमा दावों का किया भुगतान
- प्रदेश के 4 लाख से अधिक पशु और मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड जारी
- मध्यप्रदेश को लगातार 7 बार मिला कृषि कर्मण अवॉर्ड

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत  
₹ 2 लाख 25 हजार 837 करोड़ के हितलाभ किसानों को वितरित

